

किसी भी कार्य को करने से पहले वह हमेशा असंभव लगता है।

- अज्ञात

विकास की रफ्तार सुस्त

भारत में कृषि, उद्योग और सर्विसेज तीन प्रमुख घटक हैं जिनमें उत्पादन बढ़ने या घटने के औसत के आधार पर जीडीपी दर तय होती है। पिछले कुछ समय से इन तीनों ही क्षेत्रों में भारी सुस्ती दिख रही है।

मनीषा गुरुरानी

देश के विकास की रफ्तार में लगातार आ रही कमी चिंता का विषय है। शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक जुलाई-सितंबर, 2019 की तिमाही के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि की दर 4.5 प्रतिशत दर्ज की गई है। यह लगातार छठी तिमाही है, जब जीडीपी के बढ़ने की दर में गिरावट आई है। गौरतलब है कि जीडीपी किसी खास अवधि के दौरान वस्तु और सेवाओं के उत्पादन की कुल कीमत है। भारत में कृषि, उद्योग और सर्विसेज तीन प्रमुख घटक हैं जिनमें उत्पादन बढ़ने या घटने के औसत के आधार पर जीडीपी दर तय होती है। पिछले कुछ समय से इन तीनों ही क्षेत्रों में भारी सुस्ती दिख रही है। इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट 6.7 फीसदी से गिरकर सिर्फ आधा प्रतिशत रह गई है। मैनुफैक्चरिंग सेक्टर का तो बुरा हाल है जिसमें बढ़ोत्तरी की जगह आधे प्रतिशत

की गिरावट दर्ज हुई है। कृषि क्षेत्र में वृद्धि की दर 4.9 से गिरकर 2.1 फीसदी और सर्विसेज की दर भी 7.3 फीसदी से गिरकर 6.8 ही रह गई है। मुश्किल यह है कि आम उपभोक्ताओं ने हाथ बांध रखे हैं। लोग सामान नहीं खरीद रहे हैं, वे अपने रोजमर्रा के खर्च में कटौती कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे मांग पैदा हो नहीं रही है। कारोबारी दुविधा में हैं। कंपनियों को अपना प्रॉडक्शन कम करना पड़ रहा है। उनमें से कई अपने कर्मचारियों की छंटनी करने को मजबूर हो रही हैं।

दरअसल बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा न होने, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्लोडाउन की खबरें आने, आवास प्रोजेक्ट फंसने, पब्लिक

सेक्टर की कई कंपनियों व बैंकों के संकट में पड़ने और कई वस्तुओं की बढ़ती महंगाई ने लोगों को आशंकाओं से भर दिया है। वे खरीदारी और निवेश से कतरा रहे हैं। हालांकि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अगली तिमाही से हालात सुधर सकते हैं। सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पिछले दिनों जो उपाय किए हैं, उनका असर अगली तिमाही से दिखना शुरू हो जाएगा। गौरतलब है कि सरकार ने विदेशी निवेशकों से सरचार्ज हटाया और कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की। ऑटो सेक्टर की बेहतरी के लिए घोषणाएं की गईं, संकटग्रस्त रीयल एस्टेट और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों के

लिए भी कदम उठाए गए। इन सबसे बाजार में सुधार की आशा है।

संभव है, बाजार में डिमांड बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक अगले हफ्ते फिर ब्याज दरें घटाए। मगर इन सबके साथ-साथ सरकार को जॉब मार्केट पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर लोगों को बड़े पैमाने पर नौकरी मिलनी शुरू हुई तो इससे आम उपभोक्ताओं में विश्वास और उत्साह पैदा होगा। सरकार वक्त की नजाकत समझे। अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए वह दलीय भेदभाव भुलाकर सबको साथ ले और कुछ ठोस व कारगर फैसले करे। विपक्ष के लिए भी यह जिम्मेदारी दिखाने का मौका है। सरकार की आलोचना उसका अधिकार है, लेकिन सही मौके पर थोड़ी सकारात्मकता राष्ट्र का संबल बन जाती है।

देने का अवसर

राय ई. क्लीनवाचर

यदि आप खुद को वेल्यू नहीं दे सकते, महत्व नहीं दे सकते, तो आप किसी और को महत्व नहीं दे सकते। अपना महत्व, अपनी वेल्यू तभी अनुभव की जा सकती है, जब आप किसी को महत्व देते हैं। अगली बार आपको देने का मौका मिले, तो सबसे पहले अपने इंट्यूशन की सुनें और फिर तुरंत उसके अनुरूप काम करें। चाहे दें अथवा न दें। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि यदि आप नहीं दे रहे हैं, तो अपने भीतर होने वाले संवाद को सुनें। यह बताएगा कि आप अपनी आत्मा से कितने जुड़े हैं और कितने नहीं। कौन सबसे बड़ा तोहफा देता है, वो जो जरूरतमंद है या वो जो दान देना चाहता है? बेशक जो जरूरतमंद है? जब देने से पहले सोचना बंद कर देते हैं, तब आप अपने खुद के महत्व पर प्रश्नचिह्न लगा रहे होते हैं। यह न तो अच्छी बात है और न ही बुरी, यह केवल उस बात की पहचान है कि आप खुद को उस क्षण किस रूप में देखते हैं।

धर्म-दर्शन



संपादकीय

सूखे का संकट

मॉनसून में देरी ने देश में सूखे के संकट को गंभीर बना दिया है। आईआईटी, गांधीनगर द्वारा चलाए जा रहे सूखा प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के अनुसार देश के 40 फीसदी से अधिक क्षेत्रों में सूखे का संकट है जबकि ड्राउट अलर्ट वार्निंग सिस्टम (ड्यूज) के अनुसार देश के 44 फीसदी हिस्से किसी न किसी रूप में सूखे से प्रभावित हैं। चालू मॉनसून सीजन में मॉनसून का आगमन ही 8 दिन की देरी से हुआ है। साथ ही कई राज्यों में प्री-मॉनसून की बारिश भी सामान्य से काफी कम हुई है जिसकी वजह से भयावह जल संकट पैदा हो गया है और कृषि पैदावार में भी कमी आने की आशंका गहरी रही है। 20 जून को समाप्त सप्ताह के दौरान देश के 91 प्रमुख जलाशयों में 27.265 बीसीएम (बिलियन क्यूबिक मीटर) जल संग्रह हुआ। यह इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का मात्र 17 प्रतिशत है। पिछले दिनों चैनै के संकट की खबर आई। वहां इसी सप्ताह चार जलाशय सूख गए और अब बहुत कम मात्रा में पानी बचा हुआ है। संकट दूर करने के लिए वहां वेल्लोर के जोलारपेट से एक करोड़ लीटर पानी विशेष ट्रेन के जरिए भेजा जाएगा। दूसरे महानगरों का भी हाल बहुत अच्छा नहीं है। बेंगलुरु का भूजल स्तर पिछले दो दशक में 10-12 मीटर से गिर कर 76-91 मीटर तक जा पहुंचा है। दिल्ली का भूजल भी लगातार कम हो रहा है। महाराष्ट्र 47 साल का सबसे बड़ा सूखा झेल रहा है। अन्य कई राज्य भी इसकी चपेट में आ गए हैं। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार अगले एक वर्ष में जलसंकट की इस समस्या से 10 करोड़ लोग प्रभावित होंगे, वहीं 2030 तक देश की 40 फीसदी आबादी इस गंभीर समस्या की चपेट में होगी।

दूसरी तरफ ट्रंप के लिए जंग या तनाव का माहौल मुफीद हो सकता है क्योंकि अगले साल अमेरिका में आम चुनाव होने वाले हैं और ट्रंप राष्ट्रवाद के मुद्दे पर दोबारा वाइट हाउस पर अपना कब्जा चाहते हैं।

किसी तरह रुके तनाव

कमल तिवारी

शुक्र है, अमेरिका ने ईरान पर हमले का इरादा छोड़ दिया वर्ना अभी हालात क्या होते, इसकी कल्पना भी भयावह है। दरअसल ईरान द्वारा एक अमेरिकी ड्रोन मार गिराए जाने के बाद अमेरिकी प्रेजिडेंट डॉनल्ड ट्रंप ने हमले का फैसला कर लिया था लेकिन एन वक्त पर अपना निर्णय वापस ले लिया। अब ट्रंप कह रहे हैं कि वे ईरान पर कुछ और प्रतिबंध लगाएंगे। इस बीच ईरान के कई सैन्य प्रतिष्ठानों पर अमेरिका ने साइबर हमले किए, हालांकि ईरान ने इससे इनकार किया है। अमेरिकी रवैये से पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। तमाम बड़ी ताकतों ने इस पर अपनी बेचौनी जताई है। अभी ईरान पर हमले के लिए एक तरफ अमेरिका पर सऊदी अरब और इजरायल का दबाव है क्योंकि वे खाड़ी क्षेत्र में ईरान के बढ़ते दबदबे को अपने लिए खतरा मान रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रंप के लिए जंग या तनाव का माहौल मुफीद हो सकता है क्योंकि अगले साल अमेरिका में आम चुनाव होने वाले हैं और ट्रंप राष्ट्रवाद के मुद्दे पर दोबारा वाइट हाउस पर अपना कब्जा चाहते हैं। यही वजह है कि वह पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को ईरान के साथ



परमाणु समझौते के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए इसे अमेरिका के लिए बेहद खतरनाक बता रहे हैं। लेकिन हकीकत का दूसरा पहलू यह है कि ईरान के साथ उलझना अमेरिका के लिए भी काफी नुकसानदेह रहेगा। ईरान के फौजी साजो-सामान में इतना दम तो है कि अमेरिका की भरपूर घेरेबंदी के बावजूद खाड़ी क्षेत्र से कच्चे तेल की आवाजाही को लंबे समय तक बाधित रख सके। ऐसा करके वह विश्व अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल मचा सकता है।

अगर युद्ध छिड़ता है तो ब्रिटेन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इजरायल को छोड़ शायद ही कोई देश ट्रंप का साथ दे। असल में ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते को लेकर ट्रंप की राय से ज्यादातर देश सहमत नहीं हैं। चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और यूरॉपियन यूनियन का मानना है कि ईरान ने समझौते का उल्लंघन नहीं किया है। फिर रूस और चीन की कई मुद्दों पर अमेरिका से तनातनी चल रही है। ये दोनों भारत को साथ लेकर व्यापार के मामले में अमेरिका के एकतरफा कदमों का विरोध करना चाहते हैं। इन सभी देशों के राष्ट्रध्यक्ष जापान में जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान मिलने वाले हैं। यहां से एक नए कूटनीतिक समीकरण की शुरुआत हो सकती है। बहरहाल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव का असर तेल कीमतों पर पड़ना स्वाभाविक था, हालांकि उनमें वैसी तेजी अभी नहीं आई है। अलबत्ता इस तनाव का प्रभाव अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर पड़ना शुरू हो गया है। भारत की सभी एयरलाइंस ने ईरान के एयरस्पेस में न जाने का फैसला किया है, जिससे भारत से मध्य-पूर्व एशिया, यूरोप और अमेरिकी मुल्कों की दूरी और बढ़ जाएगी और इन ठिकानों का सफर महंगा हो जाएगा। पूरी दुनिया को मिलकर कोशिश करनी चाहिए कि यह तनाव किसी तरह समाप्त हो।

सूडोकू बवताल-5187		*★☆☆☆ सरा	
9	6		
4 7	8 3	9	
8 7 3	1 2		
8 9	5 1	7 6	
5 1	8 7	4 9	
2 4	6 5 7		
7 1 3		5 8	
	1		4

अपना ब्लॉग

साफ हवा में सांस लेने को हम तरस गए हैं

जितेश शर्मा। पर्यावरण और पृथ्वी को बचाने के लिए आधे दिन बहुत से सेमिनार आयोजित होते हैं। लेकिन यह कुछ लोगों तक ही सीमित रहते हैं। अगर हमें अपने पर्यावरण को बचाना है तो इसके लिए जनआंदोलन शुरू करना होगा। इसमें हर शख्स को भागीदार बनाना होगा। साथ ही कड़े कानून बनाने होंगे। आजकल लोग शादियों में उपहार के तौर पर पौधे भी देते हैं। यह एक अच्छी पहल है। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तभी हमारी नींद खुलती है। अपनी धरती को बचाने के लिए क्या हम लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं? क्या हम सब यह संकल्प नहीं ले सकते कि अपने आसपास के एक पेड़ की आजीवन देखभाल करेंगे। आज साफ हवा में सांस लेने को हम तरस गए हैं। क्योंकि विकास की अंधी दौड़ में खेती की जमीन और जंगल को हम इस कदर खत्म कर चुके हैं कि ककरी के जंगल में सबका दम घुट रहा है। हम अपने हर काम के लिए वक्त निकालते हैं, तो अपने पर्यावरण को बचाने के लिए हम चंद मिनट क्यों नहीं दे सकते?

बिहार में थानों से शराब गायब, पुलिस की सफाई-शराब चूहे पी गये

